IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 1, March 2026
Impact Factor: 8.2

समकालीन वैश्विक परिदृश्य में भारतीय विदेश नीति की चुनौतियाँ : एक बहुआयामी विश्लेषण

डॉ. सर्वेश्वर उपाध्याय

सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान)

डॉ. हरिसिंह गौर महाविद्यालय, सागर (मध्य प्रदेश)

सार (Abstract)

21वीं सदी के तीसरे दशक में भारत की विदेश नीति एक ऐसे वैश्विक वातावरण में संचालित हो रही है जो तीव्र परिवर्तन, अनिश्चितता और बहुस्तरीय प्रतिस्पर्धा से युक्त है। शीत युद्धोत्तर काल की एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था अब बहुध्रुवीयता की ओर अग्रसर है, जहाँ अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा, रूस-यूक्रेन युद्ध, तकनीकी क्रांति, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक शासन संस्थाओं की सीमाएँ अंतरराष्ट्रीय राजनीति को नई दिशा दे रही हैं। इन परिस्थितियों में भारत एक उभरती हुई शक्ति के रूप में न केवल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर रहा है, बल्कि वैश्विक दक्षिण की आवाज़ बनने और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को अधिक समावेशी बनाने का भी प्रयास कर रहा है। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य समकालीन वैश्विक परिदृश्य में भारतीय विदेश नीति के समक्ष उपस्थित भू-राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी, पर्यावरणीय और संस्थागत चुनौतियों का बहुआयामी विश्लेषण करना है तथा यह आकलन करना है कि "रणनीतिक स्वायत्तता" की अवधारणा इन चुनौतियों से निपटने में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो रही है।

मुख्य शब्द: भारतीय विदेश नीति, रणनीतिक स्वायत्तता, बहुध्रुवीय विश्व, वैश्विक दक्षिण, भू-राजनीति

Copyright to IJARSCT
www.ijarsct.co.in

DOI: 10.48175/IJARSCT-31421

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 1, March 2026
Impact Factor: 8.2

प्रस्तावना

विदेश नीति किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता, सुरक्षा और विकासात्मक आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति होती है। भारत की विदेश नीति का मूल उद्देश्य सदैव राष्ट्रीय हितों की रक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना रहा है। किंतु 21वीं सदी के तीसरे दशक में वैश्विक परिस्थितियाँ इतनी जटिल और बहुआयामी हो गई हैं कि विदेश नीति का संचालन अब केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं रह गया है। आज भारत को एक साथ कई मोर्चों पर सक्रिय रहना पड़ रहा है—चीन और पाकिस्तान से जुड़े पारंपरिक सुरक्षा प्रश्न, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, तकनीकी वर्चस्व की दौड़, जलवायु परिवर्तन, तथा बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की माँग। इन सबके बीच भारत की नीति "गुटनिरपेक्षता" से विकसित होकर "रणनीतिक स्वायत्तता" के रूप में सामने आई है, जो बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन में भारत को लचीलापन और स्वतंत्र निर्णय क्षमता प्रदान करती है।

भाग 1 : भू-राजनीतिक एवं सामरिक चुनौतियाँ

1.1 चीन की आक्रामकता और द्विपक्षीय संबंधों की जटिलता

भारत-चीन संबंध समकालीन भारतीय विदेश नीति की सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं। 2020 के बाद लद्दाख में उत्पन्न गतिरोध ने सीमा पर शांति और स्थिरता के पुराने ढाँचे को कमजोर कर दिया है। चीन की तथाकथित *"सालामी-स्लाइसिंग"* रणनीति, जिसके तहत धीरे-धीरे यथास्थिति को बदला जाता है, भारत के लिए दीर्घकालिक सामरिक चिंता का विषय है।

इसके अतिरिक्त, चीन की *"स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स"* रणनीति—जिसके अंतर्गत हिंद महासागर क्षेत्र में बंदरगाहों और सैन्य-आधारित ढाँचों का विकास किया जा रहा है—भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए चुनौती प्रस्तुत करती है। पाकिस्तान में CPEC, श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह, और म्यांमार व नेपाल में चीनी निवेश भारत के पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र को सीमित करते प्रतीत होते हैं।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 1, March 2026
Impact Factor: 8.2

चीन के साथ आर्थिक संबंधों में भी द्वंद्वात्मक स्थिति है। एक ओर व्यापारिक निर्भरता और भारी व्यापार घाटा है, वहीं दूसरी ओर सामरिक प्रतिस्पर्धा। RCEP से बाहर रहना और चीनी निवेश पर प्रतिबंध इस जटिल संतुलन को दर्शाते हैं।

1.2 पाकिस्तान के साथ संबंधों का स्थायी गतिरोध

पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। कश्मीर मुद्दा, सीमा पार आतंकवाद और पाकिस्तान की आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता किसी भी सार्थक संवाद की संभावनाओं को कमजोर करती है।

पाकिस्तान का परमाणु हथियारों से लैस होना और चीन के साथ उसका गहरा सामरिक गठजोड़ भारत के लिए *दो-मोर्चा* सुरक्षा चुनौती को जन्म देता है। इस परिदृश्य में भारत को सैन्य सतर्कता के साथ-साथ कूटनीतिक विवेक का भी परिचय देना पड़ता है।

1.3 अस्थिर पड़ोस और 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति की सीमाएँ

भारत की *'नेबरहुड फर्स्ट'* नीति का उद्देश्य पड़ोसी देशों के साथ स्थिर, सहयोगपूर्ण और विकास-आधारित संबंध स्थापित करना रहा है। किंतु म्यांमार में सैन्य तख्तापलट, अफगानिस्तान में तालिबान का सत्ता में आना, श्रीलंका का आर्थिक संकट और नेपाल-बांग्लादेश की आंतरिक राजनीतिक उठापटक ने इस नीति को चुनौतीपूर्ण बना दिया है।

इन परिस्थितियों में चीन द्वारा दी जा रही आकर्षक आर्थिक सहायता और बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ भारत की तुलना में त्वरित और बड़े पैमाने पर दिखाई देती हैं, जिससे पड़ोसी देशों का झुकाव चीन की ओर बढ़ता है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 1, March 2026
Impact Factor: 8.2

भाग 2 : आर्थिक, तकनीकी एवं पर्यावरणीय चुनौतियाँ

2.1 वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और आपूर्ति श्रृंखलाएँ

रूस-यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। ऊर्जा और खाद्य कीमतों में वृद्धि, मुद्रास्फीति और वैश्विक विकास दर में गिरावट का प्रभाव भारत पर भी पड़ा है।

हालाँकि, *'चीन+1'* रणनीति के अंतर्गत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्गठन से भारत के लिए अवसर भी उत्पन्न हुए हैं। किंतु वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा के चलते भारत को अपने बुनियादी ढाँचे, श्रम सुधार और निवेश वातावरण को और अधिक आकर्षक बनाना होगा।

2.2 तकनीकी प्रतिस्पर्धा और डिजिटल संप्रभुता

5G/6G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा तीव्र हो चुकी है। अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी वर्चस्व की इस दौड़ में भारत को अपनी स्वदेशी क्षमताएँ विकसित करनी होंगी।

डेटा स्थानीयकरण, साइबर सुरक्षा और डिजिटल व्यापार के नियम भारत के लिए नीति-निर्माण की बड़ी चुनौती हैं, क्योंकि यहाँ नवाचार और सुरक्षा के बीच संतुलन आवश्यक है।

2.3 जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय सुरक्षा

जलवायु परिवर्तन भारत की विदेश नीति का एक उभरता हुआ आयाम है। हिमालयी ग्लेशियरों का पिघलना, अनियमित मानसून और चरम मौसमी घटनाएँ न केवल आंतरिक सुरक्षा बल्कि पड़ोसी देशों के साथ जल-साझाकरण संबंधों को भी प्रभावित करती हैं।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 1, March 2026
Impact Factor: 8.2

भारत "जलवायु न्याय" की माँग करते हुए यह तर्क देता है कि विकासशील देशों पर समान दायित्व थोपना अनुचित है। साथ ही, हरित ऊर्जा संक्रमण को गति देना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है।

भाग 3 : बहुपक्षवाद और वैश्विक शासन की चुनौतियाँ

3.1 वैश्विक संस्थाओं में सुधार की माँग

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता भारत की दीर्घकालिक आकांक्षा रही है, किंतु वर्तमान शक्ति संरचना में सुधार की प्रक्रिया धीमी है। पुरानी शक्तियाँ अपने विशेषाधिकार बनाए रखने का प्रयास करती हैं। QUAD, G-20 और SCO जैसे मंचों में भारत की सक्रिय भूमिका उसकी बढ़ती कूटनीतिक क्षमता को दर्शाती है, परंतु इन मंचों के भीतर हितों के टकराव भी स्पष्ट हैं।

3.2 वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व

भारत स्वयं को वैश्विक दक्षिण की आवाज़ के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। G-20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। फिर भी, वैश्विक दक्षिण के भीतर विविध राजनीतिक और आर्थिक हितों को संतुलित करना एक कठिन कार्य है।

3.3 मानवाधिकार और लोकतंत्र पर बहस

पश्चिमी देशों द्वारा मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों के मुद्दे उठाए जाना कभी-कभी कूटनीतिक दबाव का रूप ले लेता है। भारत के लिए चुनौती यह है कि वह इन आलोचनाओं का तार्किक उत्तर देते हुए सहयोग और संवाद बनाए रखे।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 1, March 2026
Impact Factor: 8.2

भाग 4 : आंतरिक प्रतिबद्धताएँ और नीतिगत सामंजस्य

रणनीतिक स्वायत्तता बनाम गठबंधन दबाव भारत की विदेश नीति का केंद्रीय द्वंद्व है। QUAD के अंतर्गत अमेरिका के साथ सहयोग और रूस के साथ ऐतिहासिक रक्षा संबंधों का संतुलन बनाना एक जटिल कार्य है। इसी प्रकार, ईरान के साथ चाबहार परियोजना जैसी सामरिक आवश्यकताओं को अमेरिकी प्रतिबंधों के संदर्भ में आगे बढ़ाना भारत की कूटनीतिक कुशलता की परीक्षा है।

निष्कर्ष

समकालीन वैश्विक परिदृश्य में भारतीय विदेश नीति बहुआयामी चुनौतियों से घिरी हुई है। इन चुनौतियों का समाधान किसी एक नीति या गठबंधन से संभव नहीं है। भारत की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह—

- **रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए संतुलित कूटनीति अपनाए,**
- **आर्थिक और तकनीकी सामर्थ्य को अपनी कूटनीतिक शक्ति में परिवर्तित करे,**
- **बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय भूमिका निभाए,**
- **और अपने पड़ोस में स्थिरता एवं सहयोग को प्राथमिकता दे।**

इन सभी प्रयासों के माध्यम से भारत न केवल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकेगा, बल्कि एक अधिक स्थिर, न्यायसंगत और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के निर्माण में भी योगदान देगा।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 1, March 2026
Impact Factor: 8.2

संदर्भ ग्रंथ सूची (Selected Bibliography)

प्राथमिक स्रोत:

1. **भारत सरकार, विदेश मंत्रालय। (वार्षिक रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियाँ, भाषण)।**
2. **जयशंकर, एस.** (2020). ***द इंडिया वे: स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड*****। हार्परकॉलिंस इंडिया।**
3. **संसद में विदेश मंत्री/राज्य मंत्री के भाषण।**

द्वितीयक स्रोत (पुस्तकें एवं संपादित संग्रह):

1. **जोशी, योगेश।** (2022). ***द इंडिया वे: स्ट्रैटेजिक अटॉनमी इन द एज ऑफ अलाइंस*****। ब्लूम्सबरी इंडिया।**
2. **मोहन, सी. राजा।** (2015). ***मोदिज़ वर्ल्ड: एक्सपैंडिंग इंडियाज स्फीयर ऑफ़ इन्फ्लुएंस*****। हार्परकॉलिंस इंडिया।**
3. **पंत, हर्ष वी.** (एड.). (2019). ***द राउटलेज हैंडबुक ऑफ़ इंडियन फॉरेन पॉलिसी*****। रूटलेज।**
4. **मिश्र, अभिषेक** (2021). ***इंडिया एंड द USA इन द इंडो-पैसिफिक*****। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।**
5. **स्नाइडर, जैक** (एड.). (2022). ***द इंडो-पैसिफिक एजेंडा: ऑफ़शोर बैलेंसिंग, इंस्टीट्यूशन्स, एंड स्टेटक्राफ्ट*****। रूटलेज।**
6. **बाबा, रमेश।** (2023). ***इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन द 21 सेंचुरी*****। केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।**

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 1, March 2026
Impact Factor: 8.2

लेख एवं शोध पत्र:

थिंक-टैंक रिपोर्ट्स:

- **ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन** (ORF), **नई दिल्ली।**
- **इंस्टिट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस** (IDSA), **नई दिल्ली।**
- **कार्नेगी इंडिया**, **नई दिल्ली।**
- **ब्रुकिंग्स इंडिया**, **नई दिल्ली।**
- **लोवी इंस्टिट्यूट**, **सिडनी।**

अकादमिक जर्नल्स:

- ***इंडियन जर्नल ऑफ़ फॉरेन अफेयर्स***
- ***इंटरनेशनल अफेयर्स***
- ***स्ट्रैटेजिक एनालिसिस***
- ***द वाशिंगटन क्वार्टरली***
- ***जर्नल ऑफ इंडो-पैसिफिक अफेयर्स***

समाचार पत्र/विश्लेषणात्मक पोर्टल:

- ***द हिंदू*** (संपादकीय/ओपिनियन)
- ***इंडियन एक्सप्रेस***
- ***लाइवमिंट***
- ***दिप्लोमैट***
- ***एशिया टाइम्स***

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 1, March 2026
Impact Factor: 8.2

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्ट्स:

1. **संयुक्त राष्ट्र** (UN), **विश्व बैंक**, **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष** (IMF)।
2. **स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट** (SIPRI) - **रक्षा व्यय और हथियारों के हस्तांतरण पर रिपोर्ट।**
3. **विश्व आर्थिक मंच** (WEF) - **वैश्विक जोखिम रिपोर्ट।**

Copyright to IJARSCT
www.ijarsct.co.in
DOI: 10.48175/IJARSCT-31421